**प्रकाशनार्थ / प्रसारणार्थ**

# स्टेट फोकस पेपर के अनुरूप बैंक वितरित करें कर्ज– उपमुख्यमंत्री

पटना 02.02.2018

नाबार्ड की ओर से एक स्थानीय होटल में आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2018–19 को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बैंकों को नाबार्ड के फोकस पेपर के अनुरूप 1.22 लाख करोड़ ऋण कृषि, लघु उद्योग जैसे प्राथमिक क्षेत्रों को वितरित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बिहार में कृषि, पशुपालन,मछली पालन व डेयरी आदि के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। केसीसी धारक किसानों से समय से कर्ज वापसी कर ब्याज सब्सिडी का लाभ लेने की अपील की।

श्री मोदी ने कहा कि 2018–19 के बजट में डेयरी, मछली और पशुपालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड देने के प्रस्ताव का सर्वाधिक लाभ बिहार को मिलेगा। बिहार में जितने तलाब और जल जमाव क्षेत्र हैं उतना शायद ही किसी दूसरे राज्य में होगा। बिहार में मुर्गी पालन और डेयरी के क्षेत्र में भी काफी संभावना है।

ऑपरेशन ग्रीन के लिए बजट में 500 करोड़ रुपये के प्रावधान से अब टमाटर, प्याज और आलू किसानों को अपने उत्पाद सड़क पर फेंकने के लिए बाध्य नहीं होना होगा। ग्रामीण हाट–बाजारों को विकसित करने के लिए बजट में 2 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए उसे पेड़ की परिभाषा से अलग कर 'नेशनल बम्बो प्रोजेक्ट' के तहत 1290 करोड़ का प्रावधान किया गया है इससे बिहार में बड़े पैमाने पर बांस की खेती करने वाले किसानों को लाभ मिलेगा।